विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त द्वारा राज्यवार वितरित धनराशि के वितरण तथा पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 1995-96 के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या

क्रम सं॰	राज्यों के नाम	वितरित धनराशि (रु॰ लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	98.00	1650
2.	हरियाणा	93.44	263
3.	जम्मू और कश्मीर	112.83	230
4.	कर्नाटक	23.65	210
5.	मध्य प्रदेश	136.29	763
6.	पंजाब	91.69	181
7.	उत्तर प्रदेश	93.18	1500
		649.08	4797

सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित गुजरात की कल्याणकारी योजनाएं

1666. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की कुछ कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) उक्त योनजाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ दो प्रस्ताव जनमें से एक अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत और दूसरा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत-क्रमशः सितम्बर, 1996 और नवम्बर, 1996 में प्राप्त हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ दो प्रस्ताव अर्थात् एक लड़कों के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत और दूसरा लड़कियों के लिए छात्रावास योजना के अंगर्गत अक्तूबर, 1996 में प्राप्त हुए है।

(ग) और (घ) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 164.50 लाख रु॰ की निर्मुक्ति को 1996-97 में गुजरात सरकार को देय केन्द्रीय सहायता में से निधियों के आंतरिक पुनर्विनियोजन के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। वर्तमान वर्ष में 212.84 लाख रु॰ की देय शेष केन्द्रीय सहायता को निर्मुक्ति वित्त वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी। कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का प्रस्ताव, जिसमें 5.09 लाख रु॰ की धनराशि शामिल है, प्रक्रियाधीन है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ प्रस्ताव राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरणों के लिए लम्बित है।

(ङ) इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

Feasibility of setting up a passenger car plant in Visakhapatnam or Kakinada.

1667. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI SAIFULLA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Andhra Pradesh Government has requested the Central Government to examine the feasibility of setting up a passenger car plant in the port cities of Visakhapatnam or Kakinada; and

(b) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Yes, Sir. A request has been received from Andhra Pradesh Government for setting up of a passenger car plant by M/s. Maruti Udyog Limited (MUL) in the port cities of Visakhapatnam or Kakinada. Since MUL is a non-Government Company and a view on the location of the plant is therefore to be taken by MUL Board of Directors; the matter has been referred to MUL.

Supply of Rice and Wheat to the PDS Beneficiaries Below the Poverty Line at a Highly subsidised Price

1668. SHRI RAMDAS AGARWAL: SHRI PARAS CHALIHA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have decided that the "PDS beneficiaries below the poverty line" would be provided rice and wheat at 50 per cent of the issue price as reported in the 'Hindustan Times' dated the 21st November, 1996.

(b) if so, the details thereof indicating the definition of "beneficiaries below the poverty line" from income point of view;

(c) whether it is a fact that the above scheme would cost the Centre nearly Rs. 1,000 crore; and

(d) if so, by when the new scheme is likely to be implemented and whether State Governments are also required to make any countribution financially in respect of existing PDS in the States?

THE MINISTER OF FOOD ANI MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLI DISTRIBUTION (SHRI DEVENDR PRASAD YADAV): (a) to (d) The issu of streamlining the Public Distributio System with focus on the poor by provi ing rice and wheat at half the norm issue price to the population living belo the poverty line is under consideration the Government.

Trend of GEM and Jewellery Exports

1669. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of COM MERCE be pleased to state:

(a) the export figure for gem an jewellery for the last three years;

(b) whether Government have e amined the reasons for the downwar trend in export of these items;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the hike in the intere rate on post-shipment credit and routin of import documents through banks hav been factors affective the growth; and

(e) if so, Government's strategy deal with them?

THE MINISTER OF STATE OF TH MINISTRY OF COMMERCE (SHR BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Th export figures for gems and jewellery f the last three years are as follows;

(Value in US $ Millio

ITEM	1993-94	1994-95	1995-
DIAMONDS	3574.50	3937.00	4577.
GOLD JEWELLERY	308.60	421.20	480.
OTHERS	111.60	142.20	222.
TOTAL:	3994.70	4500.40	5275.

SOURCE : DGCI & S.

(b) and (c) There has been substanti growth in export in this sector over th last three years. However, recently som